रणनीति बदलना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

25 दिसम्बर, 2021

विदेश सचिव की यात्रा म्यांमार यात्रा दिल्ली के सावधान संतुलित कृत्य को दर्शाती है।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की म्यांमार की दो दिवसीय यात्रा, फरवरी में तख्तापलट के बाद किसी उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी द्वारा पहली यात्रा है। म्यांमार में सैन्य शासन के प्रति भारत का दृष्टिकोण एक सूक्ष्म पुनर्गणना की ओर इशारा करता है। शुरुआत में, भारत ने अमेरिका और यूरोप द्वारा उठाए गए कठोर रुख से दूरी बनाए रखी थी, जिसने संसद चुनावों में जीत हासिल करने के बाद आंग सान सू की और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से बाहर करने के लिए जुंटा की कड़ी निंदा की थी।

दिल्ली ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए भी अपील की थी और यहाँ तक कि इस महीने की शुरुआत में जो सू-की को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में घटाकर दो साल कर दिया गया था, उसकी निंदा भी की थी। अपनी यात्रा के दौरान, श्रृंगला ने सैन्य अधिकारियों, सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) के सदस्यों और कुछ सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात की। हालांकि, सू की के साथ मिलने की आकांक्षा (इच्छा) के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

नई दिल्ली ने म्यांमार पर एक्सट्रीम पोजिशन ले ली थी जब सेना ने 1962 में नवोदित लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था और 1990 के दशक तक भारत अपने इस स्टैंड पर कायम रहा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने जुंटा से बात-चीत करने का फैसला किया।

भारत के रुख में बदलाव इस अहसास के बाद हुआ कि पश्चिमी लोकतंत्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शासन ने म्यांमार को बीजिंग के पक्ष में जाने के लिए मजबूर कर दिया। आज स्थिति बहुत अलग नहीं है, हालांकि म्यांमार में लोकतांत्रिक आवेग, 1988 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की विरासत और 2015 से लोकतांत्रिक सरकार की आंशिक बहाली, सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में प्रकट हो रही है। तख्तापलट और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा म्यांमार को अलग-थलग करने से जुंटा बीजिंग के करीब पहुंच गया है।

नागालैंड और मणिपुर में सक्रिय विद्रोही समूहों, पहाड़ी इलाको से गुजरने वाली लंबी और छिद्रिले सीमा से भारत के संबंध भी जटिल हैं। नेपीडॉ (म्यांमार सैन्य शासन) हाल के वर्षों में भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन म्यांमार सीमा के पास मणिपुर में असम राइफल्स के एक अधिकारी और परिवार पर हालिया हमले से पता चलता है कि विद्रोही समूहों का खतरा टला नहीं है। इसके अलावा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में जनजातियों के सीमा पार अपने समकक्षों के साथ जातीय बंधन हैं, जो म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के बाद शरणार्थियों की आमद की व्याख्या करता है।

दिल्ली के लिए यह विवेकपूर्ण हो सकता है कि भारत के अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए नेपीडॉ को मनाने के लिए जुंटा के साथ जुड़े और अपने अच्छे कार्यालयी संबंधों का उपयोग करे। श्रृंगला की यात्रा संकेत देती है कि, अभी के लिए, भारत लोकतंत्र की अपनी शर्त को वापस लेने के लिए तैयार है और वास्तविक राजनीतिक संबंधों की शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति देता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में म्यांमार की यात्रा पर भारत की ओर से कौन गया था?

(क) भारत के राष्ट्रपति

(ख) भारत के प्रधानमंत्री

(ग) भारत के विदेश सचिव

(घ) भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Who had gone from India's side on a recent visit to Myanmar?

(a) President of India

(b) Prime Minister of India

(c) Foreign Secretary of India

(d) National Security Advisor of India

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत के म्यांमार में क्या हित व्याप्त हैं? भारत द्वारा चीन को प्रतिसन्तुलित करने के लिए म्यांमार में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

Q. What are the interests of India in Myanmar? What steps does India need to take in Myanmar to counterbalance China? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।